



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]  
No. 81]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2003/ज्येष्ठ 8, 1925  
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2003/JYAISTHA 8, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 23 मई, 2003

सं. टी ए एम पी/30/2003-एन एम पी टी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण विलंबित भुगतानों/प्रतिदायों पर प्रभार्य दंड ब्याज की दर में संशोधन के लिए न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन करता है।

मामला सं. टी ए एम पी/30/2003-एन एम पी टी

न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास

आवेदक

आदेश

(मई, 2003 के 6वें दिन पारित)

यह मामला विलंबित भुगतानों/प्रतिदायों पर प्रभार्य दंड ब्याज की दर में कमी करने के बारे में न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. एन एम पी टी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य बातें कही हैं :-

- (i) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने 5 नवंबर, 2001 को पारित आदेश के माध्यम से पत्तन न्यासों को भारतीय स्टेट बैंक की प्रारंभिक ब्याज दर (पीएलआर) से न्यूनतम 2% और अधिकतम 18% अधिक के बीच की सीमा में दर का चयन करने का विकल्प दिया है। पत्तन न्यासों को अपना विकल्प तत्काल प्रयोग करना चाहिए और निर्धारित सीमा के भीतर दर का चयन करना चाहिए। इसके पश्चात कोई भी बदलाव केवल इस प्राधिकरण के अनुमोदन से किया जा सकेगा।
- (ii) एन एम पी टी ने दंड ब्याज की वर्तमान 18% दर को जारी रखने का विकल्प अपनाया।
- (iii) दंड ब्याज दर की समीक्षा करने पर, एन एम पी टी ने विचार किया है कि इस दर को भारतीय स्टेट बैंक की प्रारंभिक ब्याज दर (पीएलआर) से ऊपर 2% की सीमा तक कम करना सही और उपयुक्त होगा।

3.1 यह उल्लेखनीय है कि महापत्तन न्यासों पर प्रभार्य दंड ब्याज की दरों की सीमा निर्धारित करते हुए इस प्राधिकरण ने 2 नवंबर, 2001 को एक आदेश पारित किया था।

3.2 एनएमपीटी ने इस प्राधिकरण के 5 नवंबर, 2001 को पारित आदेश के अनुपालन में 18% दंड ब्याज दर को जारी रखने का विकल्प अपनाया था। अब, इसने दंड ब्याज दर को संशोधित कर भारतीय स्टेट बैंक की प्रारंभिक ब्याज दर (पीएलआर) से ऊपर 2% के स्तर पर करने का प्रस्ताव किया है। एनएमपीटी का यह प्रस्ताव इस प्राधिकरण द्वारा पहले दिए गए उस निर्णय के अनुसार है कि दंड ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की प्रारंभिक ब्याज दर (पीएलआर) से ऊपर न्यूनतम 2% और अधिकतम 18% के बीच होगी।

4. परिणामस्वरूप, समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण एनएमपीटी के दरमान में प्रभार्य दंड ब्याज की दर से संबंधित निम्नलिखित निर्धारण को अनुमोदन प्रदान करता है :-

- (i) इस दरमान के अधीन किसी भी प्रभार के विलंबित भुगतान पर उपयोक्ता को समय-समय पर लागू भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की प्रारंभिक ब्याज दर (पीएलआर) से 2% अधिक की वार्षिक दर से ब्याज अदा करना होगा।
- (ii) पत्तन न्यास को विलंबित प्रतिदायों पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की समय-समय पर लागू प्रारंभिक ब्याज दर (पीएलआर) से 2% अधिक की वार्षिक दर से दंड ब्याज अदा करना होगा।

5. एनएमपीटी को अपने दरमान में तदनुसार संशोधन करने का निदेश दिया जाता है।

6. दंड ब्याज की संशोधित दर इस आदेश के भारत का राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख से 15 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रभावी होगी।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/III/IV/143/03 (असा.)]

### TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd May, 2003

**No. TAMP/30/2003-NMPT.**—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal from the New Mangalore Port Trust for revision of the rate of penal interest leviable on delayed payments/refunds as in the Order appended hereto.

#### Case No. TAMP/30/2003 -NMPT

The New Mangalore Port Trust

----

Applicant

### ORDER

(Passed on this 6th day of May 2003)

This case relates to a proposal received from the New Mangalore Port Trust (NMPT) about reduction in the rate of penal interest leviable on delayed payments / refunds.

2. The NMPT has made the following points in its proposal:

- (i). Through an Order passed on 5 November 2001, TAMP has given option for the Port Trusts to choose a rate in the range between a minimum of 2% above the Prime Lending Rate (PLR) of SBI and a maximum 18%. The Port Trusts must exercise their option immediately and choose a rate within the range prescribed. Any change thereafter can only be with the approval of the Authority.
- (ii). The NMPT opted for continuation of the existing rate of 18% penal interest.
- (iii). On a review of the rate of penal interest, the NMPT considers it fair and reasonable to reduce it to the level of 2% above the PLR of SBI.

3.1. It is noteworthy that this Authority had passed an Order on 5 November 2001 prescribing the range of rates of penal interest leviable at the major port trusts.

3.2. The NMPT opted to continue with the rate of 18% penal interest in compliance with the Authority's Order passed on 5 November 2001. Now, it proposes to modify the rate of penal interest to the level of 2% above the PLR of SBI. The proposal of the NMPT is in line with the decision already taken by this Authority that the rate of penal interest will be in the range between a minimum of 2% above the PLR of the SBI and a maximum of 18%.

5. In the result, and based on a collective application of mind, this Authority approves the following prescription relating to rate of penal interest leviable in the Scale of Rates of the NMPT:

- "(i). The user shall pay interest at the rate of 2% above the Prime Lending Rate (PLR) of the State Bank of India (SBI), applicable from time to time, per annum, on delayed payments of any charge under this Scale of Rates.
- (ii). The Port Trust shall pay penal interest at the rate of 2% above the Prime Lending Rate (PLR) of the State Bank of India (SBI), applicable from time to time, per annum on delayed refunds."

6. The NMPT is directed to amend its Scale of Rates accordingly.

7. The revised rate of penal interest will come into effect after expiry of 15 days from the date of notification of this Order in the Gazette of India.

A. L. BONGIRWAR, Chairman  
[No. ADVT/III/IV/143/03 (Exty.)]